vinetur

भारत 20 अक्टूबर से न्यूज़ीलैंड की कुछ वाइन पर 150% आयात शुल्क में कटौती शुरू करेगा

मुक्त व्यापार समझौते के तहत एक दशक में शुल्क घटकर 25% या 50% होगा, जिससे अधिक मूल्य वाली न्यूज़ीलैंड वाइन को फायदा मिलेगा।

मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026



भारत के साथ न्यूज़ीलैंड का मुक्त व्यापार समझौता 20 अक्टूबर से लागू होगा। इसके साथ ही न्यूज़ीलैंड की कुछ वाइन पर भारत के 150% आयात शुल्क में चरणबद्ध कटौती शुरू होगी और प्रीमियम उत्पादकों को ऐसे बाज़ार तक नई पहुंच मिलेगी, जिसे लंबे समय से आकर्षक, लेकिन इसमें प्रवेश करना कठिन माना जाता रहा है।

समझौते के तहत, पात्र न्यूज़ीलैंड वाइन पर भारत का शुल्क 10 वर्षों में घटकर 25% या 50% रह जाएगा। यह बोतल के आयात मूल्य पर निर्भर करेगा। लागत, बीमा और मालभाड़ा आधार पर 750 मिलीलीटर की जिन वाइन का मूल्य 5 अमेरिकी डॉलर से कम है, उन पर पूरा 150% शुल्क लागू रहेगा। इससे कम कीमत वाले उत्पादों को तत्काल मिलने वाला लाभ सीमित होगा।

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा आम बाज़ार के बजाय अधिक मूल्य वाली वाइन को मिलेगा। इसका यह भी अर्थ है कि बदलाव तत्काल नहीं, बल्कि धीरे-धीरे होगा। शुल्क में राहत पाने के पात्र उत्पादकों को समझौता लागू होने पर उल्लेखनीय कटौती मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद चरणबद्ध अवधि के दौरान हर साल इसमें छोटी कटौतियां होंगी।

नौ महीने की बातचीत के बाद अप्रैल में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। न्यूज़ीलैंड के विदेश एवं व्यापार मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों ने इसकी पुष्टि की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिससे इस महीने के अंत में समझौता लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। पुष्टि की प्रक्रिया को तब औपचारिक रूप दिया गया, जब न्यूज़ीलैंड के व्यापार एवं निवेश मंत्री Todd McClay ने संसद में भारत की न्यूज़ीलैंड स्थित उच्चायुक्त Muanpuii Saiawi के साथ दस्तावेज़ों का आदान-प्रदान किया।

न्यूज़ीलैंड के वाइन निर्यातकों के लिए समझौते का समय अहम है। भारत की आबादी लगभग 1.4 अरब है, लेकिन ऊंचे सीमा शुल्क, राज्य-स्तरीय करों और जटिल नियामकीय माहौल के कारण विदेशी उत्पादकों के लिए यहां का वाइन बाज़ार अब तक मुश्किल रहा है। शुल्क में राहत के बावजूद ये घरेलू बाधाएं बनी रहेंगी और संभवत: यही तय करती रहेंगी कि आयातित वाइन कहां और किस तरह प्रतिस्पर्धा कर सकती है।

फिर भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का 150% वाइन शुल्क इस श्रेणी के सामने मौजूद प्रमुख बाधाओं में सबसे ऊंचे शुल्कों में से एक रहा है। व्यावहारिक रूप से इसके चलते कई आयातित बोतलें उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग की पहुंच से बाहर रही हैं और बाज़ार या तो घरेलू उत्पादन पर केंद्रित रहा है या फिर अमीर खरीदारों के लिए आयातित वाइन पर। नई शुल्क व्यवस्था में मुख्यत: अधिक मूल्य वाले उत्पादों पर शुल्क घटने से एंट्री-लेवल ब्रांडों के मुकाबले प्रीमियम लेबलों को फायदा मिलने की संभावना अधिक है।

McClay ने इस समझौते को विदेशी बाज़ारों के एक सीमित समूह पर निर्भरता घटाने की न्यूज़ीलैंड के निर्यातकों की व्यापक कोशिश का हिस्सा बताया है। यह ऐसे समय हो रहा है जब व्यापार को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। समझौते की पुष्टि के आसपास जारी टिप्पणियों में उन्होंने कहा कि वैश्विक हालात कम अनुमानित होते जा रहे हैं, इसलिए न्यूज़ीलैंड के कारोबारों के लिए विविधता लाना, मजबूती बढ़ाना और नए अवसर तलाशना महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते से दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते बाज़ारों में से एक तक पहुंच बेहतर होगी।

दोनों देशों के व्यापक व्यापारिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। न्यूज़ीलैंड के अधिकारियों के हवाले से दिए गए आंकड़ों के अनुसार, जून तक के 12 महीनों में न्यूज़ीलैंड और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 2.3 अरब डॉलर का था। प्रधानमंत्री Christopher Luxon और Narendra Modi ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते को लागू करने के लिए ज़रूरी कानून न्यूज़ीलैंड की संसद ने 16 सितंबर को 93 के मुकाबले 29 मतों से पारित किया। विपक्षी Labour Party ने इसका समर्थन किया।

व्यापक आर्थिक संबंधों के हिस्से के तौर पर, वेलिंगटन ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता भी जताई है। समझौता लागू होने के पहले ही दिन से भारतीय वस्तुओं को न्यूज़ीलैंड में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी।

पेय उद्योग के लिए शुल्क में यह बदलाव केवल न्यूज़ीलैंड तक सीमित असर नहीं डाल सकता। वैश्विक मानकों के लिहाज़ से भारत अब भी अपेक्षाकृत छोटा वाइन बाज़ार है, लेकिन यह उन कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है जहां आय बढ़ने और शहरी मध्यम वर्ग का खर्च बढ़ने के साथ लंबे समय में खपत बढ़ने की व्यापक संभावना देखी जाती है। प्रीमियम न्यूज़ीलैंड वाइन की आसान पहुंच उन उत्पादकों के लिए विविधीकरण का नया रास्ता खोल सकती है, जो दूसरे बाज़ारों में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इससे भारत में निर्यातक देशों के बीच प्रतिस्पर्धा भी तेज़ हो सकती है, खासकर अधिक कीमत वाले खंडों में, जहां शुल्क में तरजीही दरें खुदरा कीमतों, वितरकों के मार्जिन और रेस्तरां की वाइन सूची को प्रभावित कर सकती हैं।

हालांकि, इसके फायदे सभी को समान रूप से मिलने की संभावना नहीं है। 5 अमेरिकी डॉलर की सीमा से कम कीमत वाली वाइन बेचने वाले उत्पादकों को समझौते के तहत शुल्क में कोई राहत नहीं मिलेगी और उन पर पूरा 150% शुल्क लागू रहेगा। इससे कम कीमत वाले व्यापार का बड़ा हिस्सा समझौते के मुख्य लाभ से बाहर रह जाएगा और यह धारणा मज़बूत होगी कि कम से कम वाइन के मामले में समझौता प्रीमियम उत्पादों को तरजीह देने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के आयातकों और वितरकों को शुल्क में कटौती का आकलन ऐसे बाज़ार ढांचे के संदर्भ में भी करना होगा, जो अब भी बिखरा हुआ है। शराब संबंधी नियम राज्यों के अनुसार काफी अलग-अलग हैं, कर ऊंचे हो सकते हैं और अनुपालन की ज़रूरतों से लागत बढ़ने के साथ देरी भी हो सकती है। इन कारणों से सीमा पर कम शुल्क का मतलब यह नहीं कि उपभोक्ताओं के लिए दुकानों में कीमतें अपने-आप काफी घट जाएंगी।

इसके बावजूद, नीति की दिशा स्पष्ट है। कई वर्षों तक भारत को ऐसे संभावनाशील बाज़ार के रूप में देखा जाता रहा, जहां कई वाइन निर्यातकों के लिए व्यावहारिक रूप से पहुंच के रास्ते बहुत कम थे। अब न्यूज़ीलैंड उन देशों में शामिल होने वाला है, जिन्हें अपने उत्पादों के कम से कम एक हिस्से पर कम शुल्क का औपचारिक रास्ता मिलेगा। Marlborough sauvignon blanc, pinot noir और अन्य प्रीमियम वाइन बनाने वाले उत्पादकों के लिए समय के साथ भारत में कारोबार करना अधिक व्यवहार्य हो सकता है, खासकर होटल, रेस्तरां और विशेष वाइन खुदरा दुकानों में, जहां आयातित बोतलें पहले से ही अधिक केंद्रित हैं।

यह समझौता ऐसे समय भी आया है जब कई देशों के वाइन उत्पादक कुछ परिपक्व बाज़ारों में मांग धीमी पड़ने और अन्य बाज़ारों में व्यापारिक दबाव बढ़ने के बीच नए निर्यात अवसर तलाश रहे हैं। इस परिदृश्य में भारत के बाज़ार का चरणबद्ध खुलना बिक्री में तेज़ उछाल नहीं ला सकता, लेकिन इससे न्यूज़ीलैंड की वाइनरी को ऐसे बाज़ार में प्रवेश का अधिक स्पष्ट रास्ता मिलेगा, जहां 150% शुल्क की बाधा के चलते कारोबार करना मुश्किल रहा है।